आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 17.07.2023 से 23.07.2023)

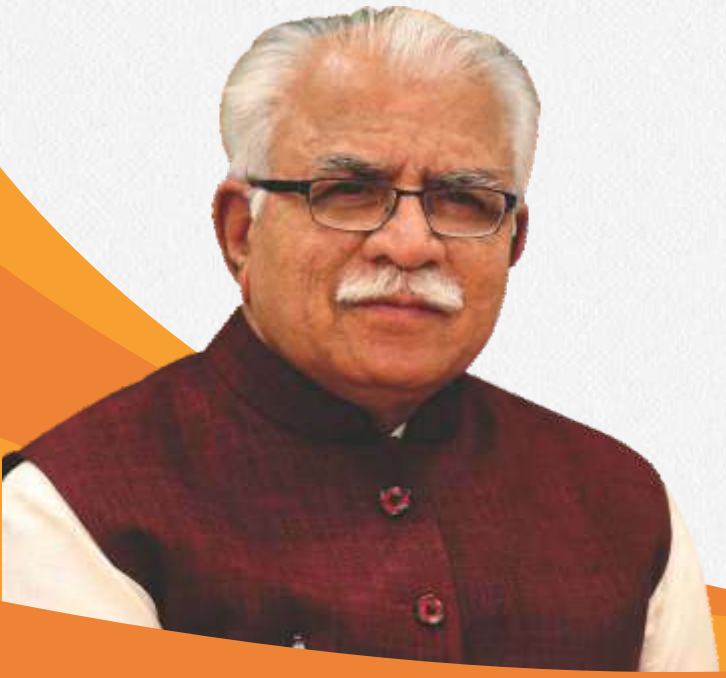

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

नशीले प्रदार्थों की तस्करी और नशे को रोकने के लिए अहम बैठक

(दिनांक 17.07.2023)

प्रभाव : माननीय केंद्रीय गृहमंत्री जी द्वारा सोनीपत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा पुलिस महानिदेशकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने नशे को रोकने के लिए देश के राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए नशे पर पूर्ण रोकथाम लगाने के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंस में शामिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंस में हरियाणा के नूंह जिले में नशे का कारोबार को खत्म करने की भी जानकारी देते हुए बताया कि 500 पुलिस कर्मियों ने नूंह में नशे के व्यापारियों को काबू किया और नशे के बड़े नेटवर्क को तोड़ा है। प्रदेश में नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम व वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया गया है, जिसमें गांव के सरपंच, संत समाज सहित अन्य मौजिज व्यक्तियों को शामिल किया गया है ताकि

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा को नशामुक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशा पीड़ितों की मदद करने के लिए अपने क्षेत्र में ड्रग पैडलिंग की गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी एकत्र करने के लिए टोल फ्री एंटी–ड्रग हेल्पलाईन नंबर 9050891508 भी शुरू किया गया है। इस नम्बर पर अब तक 5542 कॉल आई जो नशा पीड़ितों की सहायता करने और सप्लाई चौन को तोड़ने के लिए उपयोगी सिद्व हो रहा है।

गत वर्ष के दौरान राज्य में 3824 एफआईआर दर्ज कर 6000 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया। इनमें 10 नाईजीरिया के सप्लायर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 40 स्नीफर डॉग को ट्रेनिंग करवाई गई है।

एनडीपीएस एक्ट को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए लीगल एडवाईजर की सहायता ली जा रही है। राज्य में एफएसएल की भी ट्रेनिंग करवाई गई है और 8 नई एफएसएल बनाई गई है जिनमें से सिरसा में एफएसएल ने कार्य करना शुरू कर दिया है। स्टेट एक्शन प्लान बनाकर सर्वे करवाया जा रहा है जिसमें नशे से पीड़ितों के अभिभावकों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा दोषियों को पकड़ने के लिए सोफ्टवेयर तैयार किया गया है। राज्य में 52 नशामुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

नशे के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग द्वारा राज्य के सभी केमिस्ट स्टोर के लिए एक मोबाइल एप साथी तैयार किया गया है।

इस ऐप के लागू होने के बाद व्यसन के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी कोई दवा केमिस्ट द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती। इसके अलावा नशे के प्रति प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए राहगिरी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके तहत अनेक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गोहाना में जनसभा का आयोजन

(दिनांक 17.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गोहाना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जाट भवन/धर्मशाला के लिए सेक्टर 7 में भूमि देने के उपरांत सोमवार को भूमि पूजन करते हुए इसकी आधारशिला रखी।

इस अवसर पर बधाई देते हुए उन्होंने भवन में डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण हेतू 21 लाख रूपये की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश में 35 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि परिवार के नाते व्यक्ति अपने लिए घर की व्यवस्था कर लेता है, किंतु सामाजिक तौर पर सामूहिक कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार के भवन की आवश्यकता होती है। सरकार हर समाज को व्यवस्थानुसार जमीन देती है। अन्य समाजों ने भी भूमि के लिए आवेदन किया है जिन्हें जल्द ही जमीन

आवंटित की जाएगी।

2014 में उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और आज भी हम इसे बल प्रदान कर रहे हैं। जातिगत राजनीति में बांटने वाला प्रदेश का भला नहीं कर सकता। हमने छरू एस (शिक्षा, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन व सुशासन) को प्रदेश में बढ़ावा दिया है। साथ ही तीन–सी (क्राइम, करप्शन व कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स) पर करारी चोट की है। यह तीन–सी से प्रदेश का नुकसान ही हुआ है, जिसे हमने खत्म करने का काम किया है। इसका सुखद परिणाम मिला है कि आज हरियाणा उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री चलती थी, जिससे नौकरी, ट्रांसफर व सीएलयू आदि के काम बिना पैसों के नहीं होते थे। हमने भ्रष्टाचार के इस धंधे को बंद किया है, जिसका अब लोग भी समर्थन करते हैं कि योगयता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा के लिए 2741 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

(दिनांक 18.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है।

नूहं जिला के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 2741 करोड़ रुपये की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रुपये की लागत की 157 परियोजाओं का उद्घाटन तथा 1462 करोड़ रुपये की लागत की 190 परियाजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने फिरोजपुर झिरका में नूंह जिला की भी 305 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाओं को जिलावासियों को समर्पित किया। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों और विधायकों ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर

लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं नूंह से मुंडाका गांव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। यह कार्य नवंबर तक शुरू होने हो जाएगा। इसके अलावा, फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलसीपीडी करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 8 सालों से चली आ रही विकास की गति को आज की परियोजनाओं ने ऐतिहासिक बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डिजिटल माध्यम से 6 बार पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है, जिससे लगभग साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये की लागत की 1100 से अधिक परियोजनाएं जनता को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो हमारे कार्यकाल में हो रहा है, यह फर्क साफ दिखाई देता है। पिछली सरकार में भय, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद होता था, जिससे हमारी सरकार ने निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरकार ने छः एस दृ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन पर जोर दिया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब नहीं है, हर व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित समझता है और इसका ही परिणाम है कि आज दुनिया के लोग निवेश करने के लिए हरियाणा की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 8 सालों में सरकारी नौकरी के तौर पर प्रदेश में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। इन सरकारी नौकरियों को मिलाकर प्रदेश में कुल 35 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बेरोजगारी के नाम पर भ्रामक प्रचार करते हैं। कांग्रेस ने तीन सी (क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ट पॉलिटिक्स) को फैला रखा था। हमारी सरकार ने इन तीनों सी की व्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत राजनीति से भला होने वाला नहीं है, हमारा भला विकास के कार्यों करवाने वालों, जनता की भलाई के लिए काम करने वालों से होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार

ने बहुत से पोर्टल और एपलिकेशन बनाई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, जो देश में 2750 रुपये की सर्वाधिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है और शीघ्र ही इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान का असर इस जिले में भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अपनी उसी फसल का पंजीकरण करवाते थे, जो बाजार में बिकती थी या खराब होने पर उसका मुआवजा ले पाएं। लेकिन इस प्रणाली में कुछ गड़बड़ी पाई गई। कुछ खाली जमीन रहती थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। आस–पास के प्रदेश जैसे राजस्थान व पंजाब से लोगों ने खाली जमीन पर रजिस्ट्रेशन दिखाकर हमारे यहाँ फसल बेचना शुरू कर दिया था। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी हर एक एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाएं। यहां तक की खाली जमीन का भी पंजीकरण अवश्य करवाएं। 31

साप्ताहिक सूचना पत्र

जुलाई तक किसान अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन का पंजीकरण करवाएंगे तो उन्हें ईनाम के तौर पर 100 रुपये की राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं, उन सब सरकारों यानी जब से हरियाणा बना है तबसे सबसे ज्यादा पिछले 8.5 साल में हमारी सरकार ने मुआवजा किसानों को दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश में सभी प्रांतों में कई मामलों में अग्रणी है और यदि हम जनता के सहयोग से सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास और सबका प्रयास से इसी प्रकार काम करते रहेंगे तो हरियाणा का नाम दुनिया में भी बनेगा।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नूंह जिला के रानिका गांव में सेवइयां खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत पर गहरा दुरूख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार दुरूख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने इस परिवार को सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अन्य सदस्यों का अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा

(दिनांक 18.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मंगलवार को नूंह में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिला के विकास पर सरकार का फोकस है। यहां के नागरिकों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए निरन्तर विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि आज नूंह जिला निरन्तर विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समय–समय पर मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। यह मॉनिटरिंग सैल पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक खेमका की निगरानी में कार्य करेगी और तीन माह के अंतराल में कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जिला में कार्यरत सभी अधिकारी सभी मुख्य

साप्ताहिक सूचना पत्र

बिंदुओं पर तेजी से कार्य करें ताकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का जनता को बेहतर ढंग से लाभ मिले।

नूंह जिला में नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए नूंह को आंकाक्षी जिला की श्रेणी से बाहर लाना है, इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जिला को हर क्षेत्र में आगे लेकर जाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वरोजगार के लिए लघु ऋण के मामलों में गंभीरता दिखाते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें, इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिला में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। नूंह जिला में विकास कार्यों में बढ़ावा देते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और अपने जिला को प्रदेश भर में अव्वल लाना है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिला में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास व बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में क्रमवार बिंदुओं की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन–स्तर को सुधारने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने अर्थात् ''सबका साथ सबका विकास'' के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम फलती–फूलती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने के संबंध में लोगों की क्षमता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है।

स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना इस कार्यक्रम के विशिष्ट क्षेत्र हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बाढ़ के प्रभाव को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को संबोधित करना

(दिनांक 19.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ राहत के लिए हिमाचल सीएम राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता का योगदान देगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित इलाकों और लोगों को आर्थिक तथा मेडिकल सहायता सहित हर संभव मदद प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि 12 जिलों नामतः अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। 1353 गांवों और 4 एमसी क्षेत्र बारिश व बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि 8 से 12 जुलाई के दौरान राज्य में वर्षा हुई है। हरियाणा के

अधिकांश भागों के साथ–साथ पड़ोसी राज्यों– हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी अत्यधिक भारी वर्षा हुई है। इससे राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और सामान्य स्थिति बिगड़ गई। जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष द्वारा यह बयान देना कि नदियों में बढ़ते खनन के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, इस तरह के बयान अतार्किक हैं, क्योंकि

बाढ़ और खनन का कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि जनवरी में हुई बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान बाढ़ राहत कार्यों से निपटने के लिए 930 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में बारिश व बाढ़ के कारण 35 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु होने पर लोगों के परिवारों को डिजास्टर फंड में से 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाएगा। अंगों की हानि के लिए यदि दिव्यांगता 40 से 60 प्रतिशत है तो प्रति व्यक्ति 74,000 रुपये, यदि दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक है तो प्रति व्यक्ति 2 लाख 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसके अलावा, दुधारू पशुओं के लिए भी फंड के प्रावधान अनुसार सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 6629 व्यक्तियों को निकाला गया है। उनके लिए 41 राहत शिविर लगाए गए। इन शिविरों में आज भी 1744 लोग रह रहे हैं।

बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य और अन्य नागरिक आपूर्ति व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारी और लगातार

साप्ताहिक सूचना पत्र

बारिश के कारण उत्पन्न गंभीर स्थितियों की समीक्षा करने के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी के रूप में तुरंत प्रशासनिक सचिवों को नियुक्त किया और उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करने सहित सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जलभराव वाले क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर चिकित्सा के समुचित प्रबंध किये हैं। इन क्षेत्रों में 2878 मेडिकल कैंप लगाये गये हैं। इनमें लगभग 37,500 से ज्यादा मरीजों की जांच कर उनका इलाज किया गया है। 25,000 ओ.आर.एस. के पैकेट दिये गये हैं। इसके अलावा, पशुओं की देखभाल के लिए भी विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में पानी की आपूर्ति और दवाओं सहित चारा के लिए प्रावधान किया गया है। बड़े जानवरों के लिए जहां 80 रुपये प्रतिदिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं छोटे जानवरों के लिए 45 रुपये प्रति दिन की दर से सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि बारिश और बाढ़ से पूरे राज्य में 3,369 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 1477 ट्रांसफार्मर (डी.टी.) और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। इनकी मरम्मत के लिए लगभग 22.08 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित एस.ई. की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं। यह कमेटी सड़कों की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये से एक करोड़ रूपये तक के कार्य करवा सकती है। एक करोड़ रूपये से ऊपर के कार्यों को हरियाणा इंजीरियरिंग वर्क्स पोर्टल पर 7 दिनों की समय सीमा में निविदाएं आमंत्रित करके निपटाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बाढ़ से फसल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन जुलाई माह के बाद किया जाएगा। क्योंकि 31 जुलाई तक कुछ फसलों की बिजाई दोबारा से की जा सकती है। जिन इलाकों में पानी नहीं उतर पाएगा, उसके लिए अलग से विचार किया

जाएगा, लेकिन हमारे जो पहले से प्रावधान है, मुआवजा देने के वो 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से शत प्रतिशत नुकसान के लिए उस दर से मुआवजा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को आह्वान किया गया है कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी पूरी खेती योग्य जमीन का पंजीकरण करें, चाहे जमीन खाली भी हो, उस भूमि का भी पंजीकरण अवश्य करवाएं। ऐसा प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने

कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर यह नुकसान की जानकारी किसानों द्वारा डाली जाएगी, उसके बाद टीम उसका सर्वे करेगी और जैसे दृ जैसे कमेटी अप्रूव करेगी, मुआवजा दिया जाएगा। यह पोर्टल खुलने की तिथि से एक महीने के लिए खुला रहेगा।

उन्होंने नागरिकों के अपील की कि लोग सावधानी बरतें। पानी उबालकर पीएं। इस दौरान बीमारियां फैलने का डर रहता है, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ बैठक

(दिनांक 20.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करनाल लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा वार प्रबुद्ध व्यक्तियों से धरातल पर हो रहे कार्यों पर बैठक की।

अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकें कर एक ही छत के नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े उच्चाधिकारियों से लेकर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ जन समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं और जुलाई के अंत तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का कार्यक्रम है।

प्रबुद्ध व्यक्ति व अधिकारी सरकार की टीम हैं और जनता व सरकार के मध्य एक पुल का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गत दिनों हुई वर्षा के कारण

साप्ताहिक सूचना पत्र

फील्ड में कार्यक्रम नहीं हो सके, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस व एनजीओ के साथ मिलकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य मुस्तैदी से किया है। प्रबुद्ध व्यक्तियों को ऐसी आपात स्थिति में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जनहित में कार्य करना चाहिए। आमतौर पर फील्ड में यह शंका बनी रहती है कि चंडीगढ़ मुख्यालय में अधिकारी फाइल देरी से क्लीयर करते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब सीएमओ में आए हर कागज की तहकीकात होती है और कोई कागज बिना पढ़े नहीं रहता। इतना ही नहीं, कागज भेजने वाले को उसकी मांग व समस्या के बारे सूचित भी किया जाता है। उन्होंने बैठक में आए प्रबुद्ध व्यक्तियों से अनुभव पूछे तो कुछ नई चीजें सामने आई।

जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध व्यक्ति सरकार की योजनाओं व सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचायें, ताकि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा

सकें। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे पात्र नागरिकों को सबसे पहले योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हर स्कूल में जहां 100 तक विद्यार्थी हैं, उन स्कूलों में ग्रुप डी का एक पद अवश्य भरा जाएगा और एजुसेट से जुड़े कर्मचारियों को भी फुल टाइम रखने की स्वीकृति दी गई है। एचकेआरएन के माध्यम से भी ग्रुप डी के पद भरे जाएंगे। बैठक में बताया गया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की राशि का भुगतान अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक

(दिनांक 22.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से मिलकर कार्य करें और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से सरकार को अवगत करवाएं। उन्होने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनकी जानकारी लेना और कौन सी पद्धति अपनाकर आम जन को लाभ मिल सकता है, उसके बारे में सुशासन सहयोगियों को सोचना है, तभी जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं।उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14039 समस्याओं मे से 13730 को मार्क कर अपलोड कर दिया गया है और अब तक 5 जिलों में लोगों से सीधा संवाद किया

साप्ताहिक सूचना पत्र

गया है। आगामी 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जनसंवाद के तहत आई समस्याओं का निदान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी इन समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को वे स्वयं सीधे लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। अब तक लाखों लोगों से सीधी बातचीत कर चुके हैं।

ऐसे लाभार्थियों से भी सुशासन सहयोगी मिलें और उन लोगों की कोई समस्या या किसी योजना का लाभ लेने में उन्हें कोई कठिनाई आ रही हो तो उसे दूर करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ जल्द ही आगामी बैठक की जाएगी। उस बैठक में प्रगति रिपोर्ट को टेबल फोरम में लक्ष्य और दिनांक सहित विस्तार से लेकर आएं तभी उसकी विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

फिरोजपुर झिरका के गांव रनियाला स्कूल में एक भी टीचर नहीं होने का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया गया।

इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्यवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से सेवाएं बढ़ाने के लिए पीड़ितों को दाखिल कर लाभ देने बारे भी कार्यवाही करने पर विचार किया गया।

इसके अलावा ई अधिगम सेवा के तहत विद्यार्थियों को दिए टेबलेट के भी अच्छे परिणाम लाने बारे कार्य करने को कहा। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों से पानी की निकासी की जाएगी और धार्मिक 48 कोष के क्षेत्र में तालाबों को बेहतर किया जाएगा।

अकेले रहने वाले व्यक्तियों को ओल्ड एज होम का लाभ देने, प्ले वे स्कूलों का बेहतर लेवल करने बारे भी विस्तार से चर्चा की गई ताकि लोगों में इन स्कूलों के प्रति रूझान बढे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सिरसा और फतेहाबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा

(दिनांक 22.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा और फतेहाबाद जिलों में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया तथा सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य को निरंतर जारी रखने व तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ बचाव कार्यों और लोगों को तुरंत राहत पुहंचाने के लिए हरियाणा सरकार काफी गंभीरता से कार्य कर रही है। वे स्वयं सिरसा व फतेहाबाद दोनों जिलों की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा की स्थिति में सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है। इस बाढ़ के कारण लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी असेसमेंट करवाकर भरपाई की जाएगी। फसलों को हुए नुकसान का ब्योरा किसान ई–फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। ई–फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल एक महीने

साप्ताहिक सूचना पत्र

तक खुला रहेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों जिलों के अधिकारियों से कहा कि बाढ़ की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग व पशुपापाल विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सक्रियता से कार्य करें, ताकि बाढ़ के प्रभाव से होने वाली किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर संबंधित क्षेत्रों में लोगों व पशुओं का इलाज करें। उन्होंने दोनों जिलों के उपायुक्तों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, गांवों व ढाणियों में पानी के स्थिति के बारे में जानकारी ली। सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि को भी पंचायतों को जरूरत अनुसार उपलब्ध करवाया जाए। आबादी वाले क्षेत्रों को बचाने का हरसंभव प्रयास हो।

मानमुख्यमंत्री ने दोनों जिलों से एनडीआरएफ टीम व अन्य किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता के संबंध में जानकारी ली। उपायुक्त सिरसा व उपायुक्त फतेहाबाद ने बाढ़ बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दोनों जिलों के उपायुक्तों ने बताया कि जिलों में दो–दो एनडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर वॉलंटियर व समाजसेवी संस्थाएं लोगों की हरसंभव मदद कर रही हैं।

मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक

(दिनांक 22.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े 8 वर्षों में गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। नई–नई योजनाएं चलाकर समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित कर उनके जीवन को सुगम बनाया है।

राज्य सरकार का मुख्य ध्येय गरीब कल्याण है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने 6 एस– शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन पर फोकस कर हर क्षेत्र में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनता राज्य सरकार द्वारा जनसेवा के लिए किए गए कार्यों से खुश है और उनमें विश्वास बढ़ा है कि अब प्रदेश में ऐसी सरकार है, जो गरीबों व वंचितों की चिंता करती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं।

नई शिक्षा नीति को प्रदेश में 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो और बच्चे संस्कारवान भी बने। इसके अलावा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल शुरू किए हैं। साथ ही, 4 हजार प्ले–वे स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ताकि बच्चों की बुनियाद बचपन से ही मजबूत बने।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरकार ने जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा नामक नई योजना की शुरुआत की, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक लोग इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ प्राप्त कर सकें। आयुष्मान भारत योजना में पहले प्रदेश के 15 लाख परिवार कवर हो रहे थे, लेकिन चिरायु हरियाणा योजना के बाद अब प्रदेश में यह संख्या 30 लाख हो गई है। इसके अलावा, एक और नई पहल करते हुए राज्य सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना चलाई है, जिसके तहत नागरिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सही है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए अलग से थाने बनाएं हैं। वर्ष 2014 में सोनीपत में केवल एक महिला थाना था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में आज 29 महिला थाने हैं। इतना ही नहीं, बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी अलग से साइबर थाने बनाए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं, ताकि जनता उनके लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को एक राष्ट्र एक जन की सोच के साथ काम करना चाहिए तभी हम राष्ट्र के साथ जनता को जोड़ पाएंगे। जातियों, वर्गों में बंटकर यदि हम सोचेंगे तो देश को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा छोटी सोच के व्यक्ति विचार करते हैं। उदार हृद्य के व्यक्ति की सोच सारा विश्व मेरा परिवार है ऐसी होती है। इसलिए देश और समाज हित में केंद्र व प्रदेश सरकार ने जितने काम किए हैं, उन बातों को जनता तक पहुंचाएं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हर घर नल से जल के लाथार्थियों से सीधा संवाद

(दिनांक 23.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर–नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा पहला बड़ा राज्य बना है। केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा था, जिसे हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही पूरा करने का काम किया है।

जल जीवन मिशन के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिये गये हैं। इससे पहले भी वर्ष 2014 से 15 अगस्त, 2019 तक लगभग 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिये गए थे। कुल मिलाकर लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है।

संवाद के दौरान लाभार्थियों ने इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हुए कहा कि जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है, तब से उनका जीवन बेहतर बना है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अब घर में पानी की सुविधा होने से हमें दूर–दराज के क्षेत्रों में पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। लाभार्थियों ने हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें कभी दूर दराज से पानी लाने से मुक्ति मिलेगी, पर आपकी सरकार ने हमें यह सहुलियत प्रदान करके हमें बहुत बड़ा लाभ दिया है। पानी सबसे बड़ी जरूरत है, जिसे सरकार ने हम तक पहुंचाया है इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना हम सबका अधिकार है।

इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करवाने तथा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद–बूंद को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवदेनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। उनके इसी विचारों पर चलते हुए हरियाणा सरकार जल संरक्षण के लिए प्रदेश की जनता को जागरुक करने का काम कर रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घरों के अलावा हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी नल से जल पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 271 नहर आधारित जल घर तथा 229 नलकूप आधारित जल घर स्थापित किये हैं।

यही नहीं, 1457 करोड़ रुपये की लागत से 4774 नलकूप तथा 1246 बूस्टिंग स्टेशन भी स्थापित किये हैं। इनके अलावा, 3299 करोड़ रुपये की लागत से 19,515 किलोमीटर लम्बी पेयजल पाइप लाइनें बिछाई हैं। इतना ही नहीं, महाग्राम योजना के तहत 31 बड़े गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्रोतों में वृद्धि तथा मल–निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य किये गये हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागरिकों से अपील की कि सभी पानी बचाने के लिए और अधिक प्रयास करें। अगर पानी नल से व्यर्थ बहता हुआ दिखाई दे, तो उसे तुरंत बंद कर दें। कई लोग रात को नल खुला छोड़ देते हैं।

मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि रात को सोने से पहले नल बंद करके सोएं। हम सभी को जल संरक्षण या जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाने वाले लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों से भी आग्रह किया कि वे गांव में जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए काम करें। साथ ही, बारिश के पानी का संग्रह करके जल संरक्षण की दिशा मं भी

साप्ताहिक सूचना पत्र

कदम बढ़ाएं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का लगभग 10 से 15 हजार लाभार्थियों से सीधा संवाद होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी देते है वहीं लोगों से योजनाओं के फीडबैक भी लेते हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की चूक व कमी पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही भी करते है । इस कार्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम से सम्बन्धित जिलों के उपायुक्त तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़ते हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक

(दिनांक 23.07.2023)

प्रभाव : शहरी स्थानीय निकाय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक नगर निगम अपने हाउस की बैठक हर महीने आयोजित करे तथा बैठक में सभी पार्षद अपने मुद्दों को रखें। जहां तक संभव हो हर पार्षद को बोलने का मौका मिले। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़ी समस्याओं का हल निकालना हमारा प्राथमिक दायित्व है। जनता ने हमें अलग–अलग पद पर चुनकर जनता की सेवा करने का दायित्व सौंपा है। हम सभी को अपने–अपने शहर, कस्बों और गांवों का

साप्ताहिक सूचना पत्र

विकास करना है। इसलिए नगर निगम के हाउस की बैठक में अपने क्षेत्र से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को उठाएं और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला करें। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़ी समस्याओं का हल निकालना हमारा प्राथमिक दायित्व है।

जनता ने हमें अलग–अलग पद पर चुनकर जनता की सेवा करने का दायित्व सौंपा है। हम सभी को अपने–अपने शहर, कस्बों और गांवों का विकास करना है। इसलिए नगर निगम के हाउस की बैठक में अपने क्षेत्र से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को उठाएं और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला करें।

माननीय मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि करनाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को दूर करने के काम में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने आमजन से भी अपील की कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल पर स्वयं को सेल्फ सर्टिफाई नहीं किया है, वह अपनी प्रॉपर्टी की सेल्फ सर्टिफाई जरूर करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी पार्षद अपने वार्डों के विकास के कार्यों की सूची तैयार करें, इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करें।

उन्होंने कहा कि किसी भी वार्ड में पानी, सीवरेज, गली, नाली का कोई भी काम अधूरा न रहे। सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम पहले अपने बजट को खर्च करें यदि जरूरत पड़े तो विकास कार्यों के लिए सरकार बजट देने से पीछे नहीं हटेगी।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी अनप्रूव्ड कॉलोनी हैं उन्हें अप्रूव्ड करने का कार्य तेजी से चल रहा है। करनाल की भी 36 कॉलोनी जो नगर निगम में आती हैं उन्हें अप्रूव करने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जिन कॉलोनियों को अप्रूव किया जाना है उन्हें जल्द नोटिफाई किया जाएगा।

बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि प्रदान करना

(दिनांक 23.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ सरकार की सहानुभूति है। मुख्यमंत्री ने करनाल में 6 मृतकों के परिजनों को 24 लाख की सहायता राशि सौंपी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज प्रदेश के 8 जिलों में 35 लोगों के परिजनों को सहायता राशि सौंपी गई है। सभी के खाते में आरटीजीएस से पैसे पहुंच जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की वजह से आज हर व्यक्ति का डाटा है। कोई भी मुआवजा राशि देने के लिए बस उस व्यक्ति को वेरिफाई करना होता है। वेरिफाई होते ही मुआवजा राशि दे दी जाती है। किसान व अन्य कोई नुकसान के लिए हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। इस पोर्टल पर 7 दिन में वेरिफाई किया जाएगा और इसके बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। मैं स्वयं सिरसा व फतेहाबाद गया था। फतेहाबाद में पानी अभी भी गांवों में भरा हुआ है जबकि सिरसा में काफी कंट्रोल हुआ है। राजस्थान की तरफ जो पानी जाना है, उसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। पहाड़ों में बारिश हुई है। इससे यमुना व घग्गर का जलस्तर बढ़ा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नई अनाज मंडी, सोनीपत में पन्ना प्रमुखों से संवाद

(दिनांक 23.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यंत्री जी ने सोनीपत की नई अनाज मंडी में आयोजित जनसभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान की है, जिसके बूते हमारा देश विश्व के पांच ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने जा रहा है। यह हमारे आर्थिक सुधारीकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसमूह को केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आबादी के मामले में हम चीन से आगे निकल गए हैं, किंतु इस जनसंख्या में 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का आंकड़ा 60 प्रतिशत है। इन युवाओं को

साप्ताहिक सूचना पत्र

हम कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। विदेशों में बसे हमारे युवा भी हमारी आर्थिक पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं। विदेशों में कार्यरत डॉक्टरों में सर्वाधिक संख्या भारतीय डॉक्टरों की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बताया कि आज प्रदेश का एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरियाणा की पचास फीसदी हिस्सेदारी है। जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा नंबर–1 है। लगातार उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। विकास के कामों के साथ प्रदेश में सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है। ईज ऑफ लिविंग के तहत नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की जा रही है। पोर्टल बनाकर लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हरियाणा में साढ़े बारह लाख नये राशन कार्ड बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री होने के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं दर्ज होती तो दस दिन के भीतर इंतकाल सीधा संबंधित व्यक्ति के घर पहुंच जायेगा। इस प्रकार की बेहतरीन व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। आयुष्मान योजना को चिरायु योजना के माध्यम से विस्तार देते हुए करीब 29 लाख लोगों को प्रदेश में इसका लाभ दिया गया है। इस प्रकार केंद्र व राज्य में न्यायसंगत शासन व्यवस्था प्रदान की गई है।